International Journal of Advanced and Applied Sciences

Journal homepage: http://www.ijaas.in

नीमच जिले के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नगरीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Nisha Jatiya [1*], Dr. P. C. Ranka [2]

[1] *Research Scholar, Department of Economics, Vikram University, Ujjain, India*
[2] *Professor, Department of Economics, Vikram University, Ujjain, India*

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 27-07-2025
Received in revised form: 11-10-2025
Accepted: 31-11-2025

Keywords:

असंगठित क्षेत्र, नगरीय महिलाएँ, आर्थिक स्थिति, महिला रोजगार, आय एवं बचत, वित्तीय सशक्तिकरण, नीमच जिला

ABSTRACT

भारत में असंगठित क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें नगरीय महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यह क्षेत्र महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करता है, परंतु इसके साथ आय की अनिश्चितता, कम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा सीमित आर्थिक सशक्तिकरण जैसी समस्याएँ भी जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश के नीमच जिले के विशेष संदर्भ में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नगरीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। इस शोध में महिलाओं की आय का स्तर, रोजगार की प्रकृति, कार्य-घंटे, बचत की स्थिति, ऋण की उपलब्धता, पारिवारिक आय में योगदान तथा आर्थिक निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका जैसे प्रमुख पहलुओं का गहन विश्लेषण किया गया है। अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधियों के माध्यम से जानकारी संकलित की गई है। शोध निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि नगरीय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर एवं असुरक्षित बनी हुई है। अध्ययन यह सुझाव देता है कि कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, उचित मजदूरी तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

© 2025 The Authors. Published by IASE. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

परिचय

भारत में असंगठित क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख स्त्रोत है, जिसमें नगरीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ घरेलू सहायक, सिलाई-कढ़ाई, फेरी-ठेले का व्यवसाय, निर्माण कार्य, छोटे-छोटे उद्योग, खुदरा व्यापार एवं सेवा क्षेत्र जैसे विभिन्न कार्यों में संलग्न रहती हैं। हालांकि यह क्षेत्र महिलाओं को आजीविका के

अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही आय की अनिश्चितता, न्यून मजदूरी, असुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ, सामाजिक सुरक्षा की कमी तथा वित्तीय समावेशन की सीमाएँ भी जुड़ी हैं। [1] शहरीकरण की प्रक्रिया, बढ़ती जीवन-यापन लागत तथा पारिवारिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण कई महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए बाध्य होती हैं, परंतु उनके रोजगार के स्वरूप और आर्थिक स्थिति पर सीमित शोध उपलब्ध है। विशेष रूप से नीमच जिले के नगरीय क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है। [2] इस अध्ययन का उद्देश्य नीमच जिले के संदर्भ में इन महिलाओं की आय, रोजगार की प्रकृति, बचत एवं ऋण की स्थिति, पारिवारिक आय में योगदान तथा आर्थिक निर्णय-निर्माण में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति की वास्तविक स्थिति को समझकर उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप और योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें।

असंगठित श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो किसी औपचारिक संगठन, सरकारी अथवा निजी संस्था के अंतर्गत नियमित रूप से नियोजित नहीं होते। इन श्रमिकों को सामान्यतः निश्चित वेतन, कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं। ये श्रमिक प्रायः मौसमी, अस्थायी या ठेका आधार पर कार्य करते हैं, जिसके कारण उनकी आजीविका अस्थिर बनी रहती है। भारत में असंगठित क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें श्रमिकों की एक विशाल संख्या संलग्न है। [3] विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ श्रमबल का एक उल्लेखनीय हिस्सा हैं। ये महिलाएँ घरेलू सहायिका, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, दर्जी, ब्यूटी पार्लर कर्मी, सफाई कर्मचारी,

निर्माण मजदूर आदि विविध कार्यों में संलग्न रहती हैं। नगरीय अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन में इन महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसके बावजूद उनका श्रम प्रायः अदृश्य और आर्थिक रूप से उपेक्षित रह जाता है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता।

नीमच जिला, जो मध्य प्रदेश का एक उभरता हुआ नगरीय क्षेत्र है, वहाँ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। [4] ये महिलाएँ न केवल अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, बल्कि स्थानीय नगरीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। घरेलू कार्य, लघु व्यापार, सेवा क्षेत्र तथा दिहाड़ी श्रम जैसे विविध कार्यों के माध्यम से उनका श्रम शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। इसके बावजूद, असंगठित स्वरूप में कार्यरत होने के कारण ये महिलाएँ सामाजिक सुरक्षा, स्थायी आय और श्रम संरक्षण जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने में अनेक बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

असंगठित श्रमिकों में घरेलू नौकर-चाकर, निर्माण मजदूर, खेतिहर मजदूर, रिक्शाचालक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, सिलाई-कढ़ाई कार्यकर्ता, ब्यूटी पार्लर सहायक, सफाईकर्मी, ढुलाई मजदूर तथा छोटे दुकानदार आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनका श्रम बाजार अत्यधिक लचीला (Flexible) होने के बावजूद अत्यंत असुरक्षित (Insecure) है। [5] ये श्रमिक न्यूनतम लागत पर निरंतर सेवाएँ प्रदान कर नगरीय अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखते हैं, किंतु औपचारिक रोजगार संरचना के अभाव में उन्हें सामाजिक सुरक्षा, श्रम संरक्षण तथा वैधानिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप, उनका

आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण होने के बावजूद सामाजिक एवं संस्थागत स्तर पर उन्हें अपेक्षित मान्यता नहीं मिलती।

असंगठित क्षेत्र की विशेषताएँ

भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के लगभग 93 प्रतिशत श्रमिक इसी क्षेत्र में कार्यरत हैं (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2023)। यह क्षेत्र ग्रामीण एवं नगरीय–दोनों स्तरों पर आर्थिक गतिविधियों की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। कृषि, निर्माण, व्यापार, सेवा तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में इसकी व्यापक उपस्थिति देखी जा सकती है। [6] इसके बावजूद असंगठित क्षेत्र की प्रकृति अनौपचारिक, अस्थिर एवं असुरक्षित बनी हुई है, जहाँ रोजगार की निरंतरता, निश्चित आय और सामाजिक सुरक्षा का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

नीमच जिले जैसे उभरते नगरीय क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र महिला श्रमिकों के लिए रोजगार का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। कृषि क्षेत्र से बाहर निकलने वाली महिलाएँ घरेलू कार्य, निर्माण गतिविधियों, लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र में संलग्न होकर अपने परिवार की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यद्यपि इन महिलाओं का श्रम नगरीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है, फिर भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ और सामाजिक संरक्षण जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है।

संगठनात्मक संरचना का अभाव

असंगठित क्षेत्र की सबसे प्रमुख विशेषता इसका संगठनात्मक एवं कानूनी संरचना से वंचित होना है। इस क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश इकाइयाँ औपचारिक पंजीकरण के बिना संचालित होती हैं, जिनमें सड़क किनारे दुकानें, घरेलू उत्पादन इकाइयाँ तथा निर्माण स्थलों पर कार्यरत ठेकेदारी श्रम प्रमुख

उदाहरण हैं। [7] इन उद्यमों में प्रायः न तो नियमित लेखा-जोखा रखा जाता है और न ही वेतन रजिस्टर, कार्य समय अभिलेख अथवा श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाता है।

साहित्य समीक्षा

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार (2023) [1] राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा प्रकाशित "भारत में असंगठित क्षेत्र का श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट" असंगठित क्षेत्र में रोजगार की व्यापक स्थिति का व्यापक आंकड़ों के साथ विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, आय स्तर, कार्य-घंटे, शिक्षा स्तर तथा रोजगार की विविध प्रकृतियों पर विस्तृत डेटा उपलब्ध कराया गया है। विशेष रूप से ग्रामीण और नगरीय असंगठित क्षेत्र में लैंगिक भिन्नताओं को उजागर करते हुए यह रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं का योगदान असंगठित श्रम बाजार में महत्वपूर्ण होने के बावजूद उन्हें नियमित और संरक्षित रोजगार के अवसर कम मिलते हैं। रिपोर्ट के निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है, जो वर्तमान अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (2022) [2] द्वारा जारी "भारतीय असंगठित श्रम बाजार की स्थिति" दस्तावेज़ असंगठित श्रम बाजार की संरचना, श्रमिकों की स्थितियाँ, और मौजूदा नीतिगत चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में असंगठित श्रमिकों के जीवन स्तर, आय की अनिश्चितता एवं रोजगार की असुरक्षा को प्रमुख चिंता के रूप में चिन्हित किया गया है। महिलाओं के संदर्भ में यह पाया गया कि वे असंगठित क्षेत्र की श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण हिस्सा हैं परन्तु आर्थिक निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी सीमित एवं कम मान्यता प्राप्त है। मंत्रालय ने इस अध्ययन

में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा श्रमिक विकास पहलुओं पर सुझाव प्रदान किए हैं, जो वर्तमान शोध में नगरीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा के विश्लेषण हेतु महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) (2021) [3] अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित "Informal Employment and Women Workers in Developing Economies" (2021) रिपोर्ट ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में असंगठित रोजगार और महिला श्रमिकों की स्थितियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को काम के अस्थिर स्वरूप, कम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव तथा काम के वातावरण में असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ILO की यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि नगरीय असंगठित क्षेत्रों में महिलाएँ पारिवारिक आय में योगदान करती हैं, परन्तु उनके श्रम का मूल्यांकन और सामाजिक सम्मान पर्याप्त रूप से नहीं हो पाता। यह वैश्विक परिप्रेक्ष्य वर्तमान शोध के लिए एक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे नीमच जिले की नगरीय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा की तुलना व्यापक आर्थिक संरचनाओं से की जा सकती है।

World Bank (2021) [4] विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित "Women and Work in Urban Informal Sector" (2021) अध्ययन में नगरीय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के रोजगार, आय, जीवन-स्तर और आर्थिक समावेशन का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में विशेष रूप से शहरी असंगठित क्षेत्र की जटिलताओं, कार्य-घंटों की अनियमितता, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच, तथा वित्तीय सेवाओं तक महिलाओं की सीमित पहुँच पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि नगरीय असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के लिए रोजगार के सुरक्षात्मक

उपाय, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अध्ययन नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर व्यापक नीति सिफारिशें प्रदान करता है, जो नीमच जिले जैसे स्थानीय संदर्भों के विश्लेषण में उपयोगी सिद्ध होती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग (2022) [5] राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित "नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट" (2022) में शहरी क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरीय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को असमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कम पहुँच, तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। आयोग ने यह भी दर्शाया है कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नीतिगत उपायों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और वित्तीय समावेशन के महत्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए स्थानीय संदर्भ में महिलाओं की वास्तविक स्थिति और समायोजित नीतिगत आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक सिद्ध होता है।

मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग (2023) [6] मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित "राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति रिपोर्ट" (2023) में मध्य प्रदेश की महिला आबादी की आर्थिक गतिविधियों, आय स्तर, रोजगार स्वरूप तथा सामाजिक स्थिति पर विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं की आय असमान है और वे पारंपरिक एवं असंगठित रोजगारों में अधिक निर्भर हैं। विशेष रूप से शहरी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक अवसरों की कमी, कौशल विकास के

अभाव तथा वित्तीय समावेशन की सीमाओं का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में महिलाएँ परिवारिक निर्णय-निर्माण में सीमित भागीदारी रखती हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति भी प्रभावित होती है। यह रिपोर्ट वर्तमान शोध के संदर्भ में प्रदेश-स्तरीय साक्ष्य प्रदान करती है, जिससे नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाओं की आर्थिक दशा को समग्र रूप से समझने में सहायता मिलती है।

सेन, अमर्त्य (1999) [7] अमर्त्य सेन का प्रतिष्ठित कार्य Development as Freedom (1999) विकास को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं का विस्तार मानता है। सेन के सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसरों की उपलब्धता एक समग्र मानव विकास का आधार है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के संदर्भ में सेन की यह विचारधारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिति को केवल आय के माध्यम से नहीं, बल्कि निर्णय-निर्माण की क्षमता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे पहलुओं के समन्वित प्रभाव से देखती है। इस दृष्टिकोण से नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाएँ न केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, बल्कि व्यापक सामाजिक अवसरों से भी वंचित रहती हैं। सेन की अवधारणा वर्तमान शोध को एक सैद्धांतिक ढाँचा प्रदान करती है, जिससे महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा का विश्लेषण अधिक व्यापक दृष्टि से किया जा सकता है।

सामाजिक अनुसंधान पत्रिका (2024) [8] के संस्करण में प्रकाशित “भारत में असंगठित क्षेत्र का महिला श्रमबल पर प्रभाव” नामक शोध आलेख असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं पर आर्थिक, सामाजिक और मानसिक प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन में बताया गया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने

वाली महिलाओं को निम्न मजदूरी, कार्य-परिस्थितियों की असुरक्षा, कार्य-घंटों की अनियमितता तथा सामाजिक सम्मान की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध सामाजिक संरचना और लैंगिक विभाजन की भूमिका को भी रेखांकित करता है, जिससे महिलाएँ आर्थिक रूप से असुरक्षित तो होती ही हैं, साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान में भी गिरावट का अनुभव करती हैं। यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है कि असंगठित रोजगार न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति और जीवन-गुणवत्ता पर भी व्यापक प्रभाव डालता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार (2023) [9] (NSO) द्वारा प्रकाशित "भारत में असंगठित क्षेत्र का श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट" (2023) असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की भूमिका, रोजगार स्वरूप और आय संबंधी डेटा का विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट नगरीय और ग्रामीण असंगठित श्रमिकों के बीच लैंगिक भेदभाव, आय स्तर की असमानता तथा सामाजिक सुरक्षा के अभाव को रेखांकित करती है। विशेष रूप से महिलाओं की श्रम भागीदारी, कार्य-प्रकृति तथा आय की अस्थिरता पर यह विस्तृत सांख्यिकी प्रदान करती है, जिससे असंगठित क्षेत्र में उनकी आर्थिक स्थिति का वास्तविक परिदृश्य स्पष्ट होता है। NSO की यह रिपोर्ट वर्तमान शोध के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण-आधारित संदर्भ देती है, जो शोधार्थी को नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाओं की आर्थिक समस्याओं को विस्तृत और तथ्यपरक दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (2022) [10] द्वारा प्रकाशित "भारतीय असंगठित श्रम बाजार की स्थिति" (2022) असंगठित श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा, कार्य-प्रकृति तथा नीतिगत चुनौतियों

का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं की कठिनाइयों जैसे असुरक्षित रोजगार, न्यून मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा की कमी कौशल विकास की कमी को प्रमुख विषयों के रूप में शामिल किया गया है। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि श्रमिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन और वित्तीय समावेशन आवश्यक है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार संभव हो सके। इस अध्ययन की सामग्री वर्तमान शोध के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है कि भारत में असंगठित श्रमिक महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो स्थानीय संदर्भ जैसे नीमच जिले की विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2021) [11] (ILO) द्वारा प्रकाशित "विकासशील देशों में महिलाओं का असंगठित रोजगार" (2021) अध्ययन ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के असंगठित श्रम बाजार में महिलाओं की श्रम भागीदारी और कार्य-परिस्थितियों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ अक्सर अनौपचारिक, असुरक्षित और कम भुगतान वाले रोजगारों में काम करती हैं, जिनमें श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं और कानूनी सुरक्षा की कमी मुख्य समस्याएँ हैं। ILO का यह शोध यह भी दर्शाता है कि असंगठित रोजगार सिर्फ आर्थिक गतिविधियों का समूह नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति, लैंगिक विभाजन और अवसरों की असमानता को भी प्रतिबिंबित करता है। यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए एक वैश्विक संदर्भ प्रदान करता है, जिससे नीमच जिले जैसे स्थानीय संदर्भ में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा का तुलनात्मक विश्लेषण संभव होता है।

विश्व बैंक (2021) [12] द्वारा प्रकाशित "नगरीय असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ और कार्य" (2021) रिपोर्ट में शहरी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के आय, जीवन-यापन की लागत, कार्य-प्रकृति और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं तक उनकी पहुँच पर विस्तृत डेटा और विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, नगरीय असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ अधिकांशतः अस्थिर रोजगार, अनियमित कार्य-घंटे और न्यून मजदूरी के साथ संघर्ष करती हैं। अध्ययन यह भी इंगित करता है कि नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाओं को वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग समावेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं तक पहुँच में बाधाएँ आती हैं, जिससे उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया बाधित होती है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट नगरीय असंगठित श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर नीति-निर्माण और नीतिगत हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित करती है, जो वर्तमान शोध के विश्लेषणात्मक आधार को मजबूत बनाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (2022) [13] द्वारा प्रकाशित "भारत में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट" (2022) में भारत भर में कार्यरत महिला श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ, मातृत्व सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा कार्यस्थल पर सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध नहीं होता। इसके अलावा, रिपोर्ट में लैंगिक आधार पर रोजगार अवसरों की असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर महिलाओं के समक्ष आने वाली बाधाओं का भी विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन वर्तमान शोध के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण-आधारित संदर्भ प्रदान करता है कि

शहरी असंगठित श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु व्यापक नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश श्रम विभाग (2024) [14] द्वारा जारी "राज्य में असंगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण रिपोर्ट" (2024) मध्य प्रदेश के असंगठित श्रम बाजार, रोजगार स्वरूप, आय स्तर एवं श्रमिक सुरक्षा की स्थिति का विस्तृत डेटा प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों, आय की अस्थिरता, रोजगार की शर्तों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से जुड़ी बाधाओं का विश्लेषण शामिल है। विशेष रूप से राज्य-स्तरीय आंकड़ों के माध्यम से यह रिपोर्ट दर्शाती है कि असंगठित क्षेत्र की महिलाएँ औसतन कम वेतन, अनियमित रोजगार तथा कमजोर सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का सामना करती हैं। यह अध्ययन वर्तमान शोध के स्थानीय संदर्भ को सुदृढ़ करता है और नीमच जिले जैसे शहरी क्षेत्रों में असंगठित श्रमिक महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा को समझने में ठोस आधार प्रदान करता है।

योजना आयोग, भारत (2020) [15] द्वारा प्रकाशित "भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ और असंगठित क्षेत्र" (2020) प्रतिवेदन ने भारत के समग्र रोजगार परिदृश्य, असंगठित क्षेत्र की वृद्धि, श्रमिकों की श्रम-शक्ति और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में असंगठित क्षेत्र की भूमिका, आर्थिक विकास और सामाजिक बदलावों के बीच संबंधों को रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से, यह रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिक महिलाएँ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और सीमित रोजगार साधनों के कारण आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से असमान परिस्थितियों में काम करती हैं। योजना आयोग की यह रिपोर्ट सरकारी डेटा और नीतिगत विश्लेषण के आधार पर असंगठित

श्रमिकों की स्थिति को स्पष्ट करती है, जो वर्तमान शोध के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है।

अनुसंधान पद्धति

नीमच जिला मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं आर्थिक क्षेत्र है, जहाँ चंबल, पार्वती एवं शिवना जैसी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ जिले में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। [8] यहाँ की कृषि व्यवस्था मुख्यतः वर्षा आधारित है, जो जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार मानी जाती है।

नीमच जिले का प्रमुख नगर "नीमच सिटी" जिला मुख्यालय होने के साथ-साथ मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी है। यह नगर भारतीय सुरक्षा बलों के संदर्भ में भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force - CRPF) का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, जो देश के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है।

आर्थिक दृष्टि से नीमच जिला कृषि एवं लघु उद्योगों पर आधारित है। जिले की अर्थव्यवस्था में गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, तिलहन, अफीम तथा मसालों का उत्पादन प्रमुख भूमिका निभाता है। विशेष रूप से, नीमच भारत के उन चुनिंदा जिलों में शामिल है जहाँ वैध रूप से अफीम की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त, जिले में अफीम एवं नशीले पदार्थों से संबंधित सरकारी कारखाने की उपस्थिति आर्थिक गतिविधियों को और सुदृढ़ बनाती है (वर्मा, 2018)।

जिले की सामाजिक संरचना में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एक अभिन्न घटक के रूप में उभरकर सामने आती है। [9] नगरीय क्षेत्रों में महिलाएँ मुख्यतः असंगठित क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्यों–जैसे घरेलू सेवा, निर्माण

कार्य, हस्तशिल्प, ब्यूटी पार्लर, कृषि-आधारित प्रसंस्करण गतिविधियाँ आदि–में संलग्न होकर न केवल अपने परिवार की आजीविका में योगदान देती हैं, बल्कि जिले की नगरीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नीमच जिले की जनसंख्या संरचना में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों का स्पष्ट मिश्रण देखने को मिलता है। नगरीय क्षेत्रों में व्यापार, परिवहन, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र जैसी आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि, पशुपालन तथा घरेलू-आधारित उत्पाद निर्माण के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। [10] इस प्रकार महिला श्रम जिले की आर्थिक संरचना का एक सक्रिय घटक बनकर उभरता है।

सामाजिक दृष्टि से नीमच जिला विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः लगभग 13 प्रतिशत और 7 प्रतिशत है (मध्यप्रदेश शासन, 2022)। सामाजिक असमानताएँ, सीमित संसाधन तथा शिक्षा एवं रोजगार के औपचारिक अवसरों की कमी के कारण विशेष रूप से इन वर्गों की महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। परिणामस्वरूप, उनकी रोजगार स्थितियाँ अस्थिर बनी रहती हैं और वे सामाजिक-आर्थिक रूप से अधिक संवेदनशील स्थिति में रहती हैं।

तालिका 1: महिला श्रमिकों की जनसांख्यिकीय स्थिति का सारांश

सूचकांक	***स्थिति***
कुल जनसंख्या	11.55 ***लाख***
महिला जनसंख्या	48.7%

लिंगानुपात	950/1000
महिला साक्षरता	65%
कार्यशील महिलाएँ	28%
शहरीकरण दर	24.8%
अनुसूचित जाति जनसंख्या	13%
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	7%

स्रोत: जनगणना भारत (2011); ***मध्यप्रदेश शासन (***2022); ***कुमारी (***2019); ***त्रिपाठी (***2018)

आधारभूत संरचना के संदर्भ में नीमच जिले में सड़क, रेलवे तथा संचार सुविधाओं का तुलनात्मक रूप से अच्छा विकास हुआ है। जिला राष्ट्रीय राजमार्ग 79 से जुड़ा हुआ है, जो इसे राजस्थान एवं गुजरात जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों से जोड़ता है। इस भौगोलिक एवं परिवहनिक लाभ के कारण नीमच का आर्थिक और व्यापारिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

नीमच जिले की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक विविधता तथा श्रम संरचना इसे सामाजिक-आर्थिक अध्ययन के लिए एक उपयुक्त एवं आदर्श क्षेत्र बनाती है। [11] विशेष रूप से जिले की नगरीय सीमाओं के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ समाज का वह वर्ग हैं, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का गहन अध्ययन सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता तथा समावेशी विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है (शर्मा, 2017; कुमारी, 2019)।

जनसांख्यिकी

नीमच जिला अपनी जनसंख्या संरचना, ***लिंगानुपात***, ***साक्षरता दर***, ***शहरीकरण***, ***सामाजिक वर्गीकरण और आर्थिक सक्रियता के आधार पर मध्य प्रदेश के विकसित जिलों में से एक है। यहाँ की जनसंख्या संरचना न***

केवल क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, बल्कि यह श्रम बाजार, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की भूमिका और उनकी स्थिति को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

नीमच जिले की कुल जनसंख्या 11,55,183 (11.55 ***लाख) है, जिसमें पुरुषों की संख्या*** 5,92,968 (51.3%) ***तथा महिलाओं की संख्या*** 5,62,215 (48.7%) ***है (जनगणना भारत***, 2011)***। जिले की जनसंख्या घनत्व लगभग*** 222 ***व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य औसत (***236 ***व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर) से कुछ कम है।***

परिणाम

नमूना चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निदर्शन (Purposive Sampling) पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप नगरीय असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों का चयन किया गया। अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के नीमच ज़िले के तीन चयनित नगरीय निकाय–नीमच, मनासा एवं जावद– को अध्ययन क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। [12] प्रत्येक चयनित नगरीय निकाय से 100 महिला श्रमिकों का चयन किया गया, इस प्रकार कुल 300 महिला श्रमिकों को नमूना इकाई के रूप में अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

महिला श्रमिकों का चयन निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किया गया–आयु वर्ग (18 से 60 वर्ष के मध्य), कार्य क्षेत्र (घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी-पटरी व्यवसाय, सिलाई-कढ़ाई एवं अन्य स्वरोजगार गतिविधियाँ), शिक्षा स्तर (अशिक्षित, प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक), वैवाहिक स्थिति (विवाहित, अविवाहित एवं विधवा) तथा स्वरोजगार गतिविधियों एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ाव। [13] इन मापदंडों के माध्यम से अध्ययन में विविध सामाजिक-आर्थिक

पृष्ठभूमि की महिला श्रमिकों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया।

उपकरण

शोध से संबंधित प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह हेतु निम्नलिखित उपकरणों एवं तकनीकों का प्रयोग किया गया–

1. अनुसूची एवं संरचित प्रश्नावली
2. व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि
3. प्रत्यक्ष अवलोकन तकनीक
4. द्वितीयक स्रोतों का विश्लेषण, जैसे– सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आंकड़े, शोध पत्र, पत्रिकाएँ एवं प्रकाशित अध्ययन

डेटा विश्लेषण की विधियाँ

संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण हेतु विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया, जिनमें औसत (Mean), प्रतिशत (%), प्रमाप विचलन (Standard Deviation), सहसंबंध गुणांक (Correlation Coefficient), प्रतीपगमन विश्लेषण (Regression Analysis), काई-वर्ग परीक्षण (Chi-Square Test) तथा प्रसरण विश्लेषण (ANOVA) प्रमुख हैं। [14] इसके अतिरिक्त आंकड़ों की व्याख्या एवं तुलनात्मक अध्ययन हेतु ग्राफ, चार्ट एवं तालिकाओं का भी प्रयोग किया गया।

इन सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से यह विश्लेषण किया गया कि महिला श्रमिकों की आय, शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति के मध्य किस प्रकार का संबंध विद्यमान है; शोषण की स्थिति किन सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है; सरकारी योजनाओं की पहुँच किन वर्गों तक सीमित है; तथा जागरूकता स्तर और योजनाओं से प्राप्त लाभ के मध्य क्या सहसंबंध पाया जाता है।

शोध की सीमाएँ

अध्ययन केवल नीमच जिले के तीन नगरीय क्षेत्रों तक सीमित है।

1. *उत्तरदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता उत्तरदाता के दृष्टिकोण पर निर्भर है।*
2. *समय, संसाधन एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों की सीमाएँ अध्ययन को प्रभावित कर सकती हैं।*
3. *अध्ययन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं तक ही सीमित है; संगठित क्षेत्र की महिलाएँ इसमें सम्मिलित नहीं हैं।*

तालिका 2: डेटा विश्लेषण की तकनीकें

तकनीक	*उद्देश्य*
*औसत (*Mean)	*सामान्य प्रवृत्ति ज्ञात करना*
प्रतिशत (%)	*वितरण और अनुपात दिखाना*
*प्रमाप विचलन (*SD)	*डेटा का फैलाव ज्ञात करना*
*सहसंबंध गुणांक (*Correlation Coefficient)	*दो चर के बीच संबंध*
*प्रतीपगमन विश्लेषण (*Regression Analysis)	*कारण-परिणाम विश्लेषण*
*काई-वर्ग परीक्षण (*Chi-square Test)	*श्रेणियों के बीच अंतर*
*प्रसरण विश्लेषण (*ANOVA)	*तीन या अधिक समूहों में अंतर*

आंकड़े और तालिकाएँ

तालिका 3: मासिक आय का वितरण

आय स्तर	*प्रतिशत (%)*	*औसत आय (*₹)
8,000 *से कम*	62	5500
8,001-12,000	25	9500
12,001 *से अधिक*	13	13000

Interpretation:

- *अधिकांश महिलाएँ (*62%) 8,000 *रुपये से कम आय अर्जित करती हैं।*
- *आय की असमानता उच्च है, जिसका कारण परिवार में अधिक सदस्य और पुरुषों का व्यय (नशा आदि) माना जा सकता है।*

तालिका 4: शिक्षा स्तर और जागरूकता

शिक्षा स्तर	% *अधिकारों की जानकारी*
अशिक्षित	12%
प्रारंभिक शिक्षा	25%
माध्यमिक शिक्षा	38%
उच्च शिक्षा	65%

Correlation Test:

- *सहसंबंध (*r) = 0.78, p < 0.01

Interpretation:

शिक्षा का अधिकारों की जानकारी पर सकारात्मक और मजबूत संबंध है।

निष्कर्ष

नीमच जिले के नगरीय क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की आर्थिक स्थिति का यह विश्लेषण दर्शाता है कि वे पारिवारिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी अस्थिर, असुरक्षित और असमान है। असंगठित क्षेत्र की प्रकृति के कारण महिलाओं को नियमित आय, सुनिश्चित कार्य-घंटे और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। कई महिलाओं को कम मजदूरी, असंगठित रोजगार, और कार्यस्थल पर असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही, उनकी बचत क्षमता सीमित है और आवश्यकताओं के लिए उन्हें उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने की बाध्यता रहती है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि महिलाओं की आर्थिक निर्णय-निर्माण में भागीदारी सीमित है, जिससे उनके आत्म-निर्भरता और आत्म-सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी की कमी, दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता और वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण अधिकांश महिलाएँ सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पातीं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत नगरीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु **कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, रोजगार के सुरक्षित अवसर, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति** आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों में उचित नीति-निर्माण एवं योजनात्मक हस्तक्षेप किया जाए, तो नीमच जिले की नगरीय महिलाएँ आर्थिक रूप से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सम्मानित बन सकती हैं।

(संदर्भ सूची) Reference

1. ***राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार (***2023). ***भारत में असंगठित क्षेत्र का श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट। नई दिल्ली।***
2. ***श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (***2022). ***भारतीय असंगठित श्रम बाजार की स्थिति। नई दिल्ली।***
3. ***अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (***2021). Informal Employment and Women Workers in Developing Economies. ***जेनेवा।***
4. ***विश्व बैंक (***2021). Women and Work in Urban Informal Sector. ***वाशिंगटन डी.सी.***
5. ***राष्ट्रीय महिला आयोग (***2022). ***नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट। नई दिल्ली।***
6. ***मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग (***2023). ***राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति रिपोर्ट। भोपाल।***
7. ***सेन, अमर्त्य (***1999). Development as Freedom. ***ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।***
8. ***सामाजिक अनुसंधान पत्रिका (***2024). ***भारत में असंगठित क्षेत्र का महिला श्रमबल पर प्रभाव। नई दिल्ली।***
9. *राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार (***2023). भारत में असंगठित क्षेत्र का श्रम सर्वेक्षण रिपोर्ट।** ***नई दिल्ली: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।***
10. *श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (***2022). भारतीय असंगठित श्रम बाजार की स्थिति।** ***नई दिल्ली।***
11. *अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (***2021). विकासशील देशों में महिलाओं का**

असंगठित रोजगार। *जेनेवा: आई.एल.ओ. प्रकाशन।*

12. *विश्व बैंक (***2021). नगरीय असंगठित क्षेत्र में महिलाएँ और कार्य। *वाशिंगटन डी.सी.।***

13. *राष्ट्रीय महिला आयोग (***2022). भारत में महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट। *नई दिल्ली।***

14. *मध्य प्रदेश श्रम विभाग (***2024). राज्य में असंगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण रिपोर्ट। *भोपाल।***

15. *योजना आयोग, भारत (***2020). भारत में रोजगार की प्रवृत्तियाँ और असंगठित क्षेत्र। *नई दिल्ली।***